

तिथि 18 सितम्बर 2025

समय 18:10

मुख्य समाचार:-

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आई टी आई में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव किए - किसानों को सशक्त बनाया।
- उद्योग जगत ने अगली पीढ़ी के जी एस टी सुधारों को कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने वाले बताया।
- हरियाणा में आज भी सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी।
- हरियाणा की विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटीं बेटियों का भिवानी में स्वागत।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की वार्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आई टी आई का उन्नयन उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले दो-तीन वार्षिक बजट में सरकार ने श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रावधान किए हैं।

सेवा और सुशासन, अर्थात् जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज, इस विशेष श्रृंखला - "सेवा पर्व" में, हम आपके

लिए लाए हैं कि कैसे मोदी सरकार ने कृषि में परिवर्तन लाया है और किसानों को सशक्त बनाया है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। यह लाखों परिवारों का भरण-पोषण ही नहीं करती, राष्ट्र की पहचान को भी परिभाषित करती है। इस अमृत काल में, सशक्त किसान देश को आत्मनिर्भरता से खाद्य उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 वर्षों में, कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है कि भारत के किसान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 81 प्रतिशत से 226 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले छह वर्षों में तीन लाख नब्बे हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 3000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 25 लाख किसानों को नामांकित किया गया है।

ऋण तक आसान और किफायती पहुँच प्रदान करने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। किसानों के लिए कुछ अन्य प्रमुख योजनाएँ भी हैं जिनमें प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम पोर्टल) शामिल हैं।

अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़

उद्योग जगत विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 22 सितंबर से लागू होने जा रहे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लेकर उत्साह का माहौल है।

इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला ने कहा है कि नई व्यवस्था से कारोबार करने में आसानी होगी और कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यलय में सेवा पखवाड़े के दौरान 2 अक्टूबर तक लोक कल्याण मेलो का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया इस को लेकर नगर परिषद की टीम ने आज लोगो को बताया कि वह बिना गारंटी के किस प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का मक़सद लोगो को आत्मनिर्भर बनाना है।

पलवल जिले में 'सेवा पखवाड़ा' के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। सरकार की ओर से मनाए जा रहे 'सेवा पखवाड़ा' के दूसरे दिन जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने गांव मांदकौल में स्वयं झाड़ू लगाकर साफ-सफाई की और ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

खरीफ सीजन के लिए जींद जिले की सभी मंडियों में सभी प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। जींद अनाज मंडी सचिव संजिव जांगड़ा ने आज बताया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए किसी तारीख की विधिवत कोई घोषणा नहीं हुई है, किंतु एक अक्टूबर से खरीद आरंभ होने की संभावना है। उन्होंने बताया –

हरियाणा में धान कटाई का सीजन शुरू होते ही कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो गया है। इस बार किसानों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई फसल अवशेष में आग लगाता है तो उस पर मामला दर्ज होगा, भारी जुर्माना लगेगा और 2 साल तक उसकी फसल का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।

निगरानी के लिए सेटेलाइट तकनीक का सहारा लिया जाएगा।

ब्रिटेन के लिवरपूल में हुई विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी भिवानी की बेटी जैस्मिन लंबोरिया, रजत पदक जीतने वाली नुपूर और कांस्य पदक लेकर लौटी पूजा बोहरा का भिवानी पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैस्मिन लंबोरिया ने कहा –
